



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39176

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 2105/2026

विकास

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	मोहम्मद कैस, नेहा रानी, सत्यवेंद्र सिंह यादव
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए., लाल बहादुर

कोर्ट नं. - 65

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी

- कार्यालय ने दिनांक 19.02.2026 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताया है कि मामले के पहले सूचनाकर्ता को जारी नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया गया है, नोटिस तामील करने के बावजूद, कोई भी सूचनाकर्ता या उच्च न्यायालय कानूनी सेवाओं के लिए उपस्थित नहीं हुआ है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पीड़ित की आयु लगभग 17, 1/2 वर्ष है। उन्होंने आगे कहा कि पीड़िता ने कहा था कि प्यार और स्नेह के कारण, वह आवेदक के साथ गई थी और शादी कर ली थी। शारीरिक संबंध भी स्थापित किए गए थे, लेकिन कोई विवाह कभी संपन्न नहीं हुआ था। उसने यह भी कहा है कि आवेदक उसे जबरन लखनऊ ले गया और धमकी दी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, पीड़िता बड़ी है और एक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सहमति देने वाली पार्टी है, हालांकि उसके 183 बी.एन.एस.एस. बयान में कहा गया है कि आवेदक उसे जबरन लखनऊ ले गया था और धमकी दी थी, लेकिन इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि शारीरिक संबंध जबरन स्थापित किए गए थे। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक को गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों की असत्यता को प्रदर्शित करने के लिए कई अन्य प्रस्तुतियाँ भी न्यायालय के समक्ष रखी गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया है कि वह कानून की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी, ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर लागू करना उचित समझे। इसके बाद उन्होंने कहा कि आवेदक 16.08.2025 से जेल में बंद है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. के साथ-साथ सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक की बेगुनाही को पूर्व परीक्षण चरण में नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए, वह किसी भी भोग के लायक नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त होगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ, साक्ष्य की प्रकृति, और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। इसलिए जमानत आवेदन की अनुमति है।

7. बी.एन.एस. की धारा 137(2), 87, 64(1) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4(1) के तहत 2025 के केस क्राइम नंबर 154 में शामिल आवेदक विकास को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी या परेशान नहीं करेगा।
 - iii) आवेदक ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
 - iv) आवेदक उस अपराध के समान अपराध नहीं करेगा जिसके लिए आवेदक पर आरोप लगाया गया है, या आयोग का संदेह है।
 - v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।
8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(डॉ. न्यायमूर्ति गौतम चौधरी)

फ़रवरी 20, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"